भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- †*58

उत्तर देने की तारीख- 28/11/2024

पीएम जनमन योजना

†58* श्री हरीभाई पटेल:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान के आरंभ के उपरांत इसके लाभार्थियों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) शिक्षा और कौशल विकास सम्बन्धी पीएम जनमन योजना का जनजातीय युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है तथा इससे संबन्धित प्रासंगिक आंकड़े और लाभार्थियों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं; और

(ग) अगले पांच वर्षों के लिए पीएम जनमन योजना के प्राथमिक उद्देश्यों और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और ये जनजातीय विकास के समग्र लक्ष्यों के किस प्रकार अनुरूप हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
(श्री जुएल ओराम)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

"पीएम-जनमन योजना" के संबंध में श्री हरीभाई पटेल द्वारा दिनांक 28.11.2024 को उठाए गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या †*58 के उत्तर हेतु भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): 15 नवंबर 2023 को, माननीय प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) का शुभारंभ किया। मिशन का उद्देश्य तीन वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा तक बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य और पोषण , सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। लगभग 29000 बस्तियों में रहने वाले 11 लाख पीवीटीजी परिवारों को 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से मिशन के अंतर्गत कवर किया गया है। तीन वर्षों के लिए मंत्रालय-वार एवं उपाय-वार मिशन लक्ष्य **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

अभियान योजना के तहत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक दिए गए लाभों का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी 2024 को विभिन्न राज्यों के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की थी, जब पीएम जनमन के तहत घरों के निर्माण के लिए पहली किस्त जारी की गई थी और अन्य लाभ स्वीकृत किए गए थे। शिवपुरी (मध्य प्रदेश), अल्लूरी सीतारन राजू (आंध्र प्रदेश), बारां (राजस्थान) और जशपुर (छत्तीसगढ़) के लाभार्थियों ने पुन: 15 नवंबर 2024 को जमुई, बिहार में उनके साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत उनके गांवों में विभिन्न विकास गतिविधियाँ किस प्रकार शुरू की गई हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन/विभागों के माध्यम से पीएम पीएम जनमन के तहत गांवों और बस्तियों में रहने वाली पीवीटीजी आबादी को कवर करने के लिए पीवीटीजी आबादी के आंकड़ों और बुनियादी ढांचे के अंतरों का अनुमान लगाने हेतु पीएम गति शक्ति मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से बस्ती स्तर डेटा संग्रह करने का कार्य शुरू किया है। एकत्र किए गए डेटा (21.11.2024 तक) के आधार पर, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, पीवीटीजी जनसंख्या को **अनुलग्नक-III** में सारणीबद्ध किया गया है।

पीएम जनमन के अंतर्गत, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 194 छात्रावासों को मंजूरी दी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइफेड द्वारा पीएम जनमन के अंतर्गत 501 वन धन विकास केंद्रों को भी मंजूरी दी गई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के एनआईईएसबीयूडी के माध्यम से कुल 259 वीडीवीके के अंतर्गत आने वाले लगभग 15000 लाभार्थियों को उद्यमिता, कौशल विकास और मूल्य संवर्धन पर प्रशिक्षण दिया गया है।

अनुलग्नक - I

मंत्रालय का नाम	गतिविधि	मिशन लक्ष्य (2023-2026)
ग्रामीण विकास मंत्रालय	पक्के मकानों का प्रावधान	4.90 लाख घर
	संपर्क मार्ग	8000 किमी सड़क
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सचल औषद्यालय इकाइयाँ	1000 एमएमयू
जल शक्ति मंत्रालय	पाइप द्वारा जलापूर्ति	15309 गांव
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण एवं संचालन	2500
शिक्षा मंत्रालय	छात्रावासों का निर्माण और संचालन	500
संचार मंत्रालय	मोबाइल टावरों की स्थापना	3959 बस्तियों को कवर करना
विद्युत मंत्रालय	अविद्युतिकृत घरों का विद्युतीकरण	2.65 लाख आवास (एचएच)
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	आवासों (एचएच) का विद्युतीकरण	सभी पात्र एवं विद्युत मंत्रालय द्वारा कवर नही किये गये
जनजातीय कार्य मंत्रालय	बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी)	1000
	वीडीवीके की स्थापना	500

अनुलग्नक -II

"पीएम-जनमन योजना" के संबंध में श्री हरीभाई पटेल द्वारा दिनांक 28.11.2024 को उठाए गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या †*58 के उत्तर हेतु भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

पीएम जनमन प्रगति (20 नवंबर 2024 तक)

मंत्रालय का नाम	**उपाय**	**मिशन लक्ष्य (2023-2026)**	स्वीकृतियां	**वास्तविक उपलब्धियाँ**	**वित्तीय स्वीकृतियां (करोड़ रुपए में)**
ग्रामीण विकास मंत्रालय	पक्के मकान	~ 4.90 लाख पक्के मकान	336367 घर	59487 मकान पूरे हो गये।	2722.14
	संपर्क मार्ग	8000 किमी सड़क	4484.30 किमी सड़क	11.51 किलोमीटर सड़क पूरी हुई	3386.2
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सचल औषद्यालय इकाइयाँ (एमएमयू)	1000 एमएमयू	616 एमएमयू	616 एमएमयू कार्यरत हैं जिनमें 25 लाख से अधिक व्यक्ति आते हैं।	208.7
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय	पाइप द्वारा जलापूर्ति (एफएचटीसी)	15309 गांव	6350 गांव 100% संतृप्त	6350 गांव 100% संतृप्त	344.35
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी)	2500 आंगनवाड़ी केन्द्र	1864 आंगनवाड़ी केन्द्र	770 आंगनवाड़ी केन्द्रों को चालू किया गया।	311.16
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय	छात्रावास	500 छात्रावास	194 छात्रावास	-	476.16
दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय	मोबाइल टावर	3959 बस्तियों को कवर करना	1499 बस्तियाँ	406 बस्तियां कवर की गईं	204.3
विद्युत मंत्रालय	आवासों (एचएच) का विद्युतीकरण	~ 2.65 लाख आवास (एचएच)	140440 आवास (एचएच)	87132 आवास (एचएच) विद्युतीकृत	516.15
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	आवासों (एचएच) का विद्युतीकरण	सभी पात्र और विद्युत मंत्रालय द्वारा कवर नहीं किये गये	9569 आवास (एचएच)	800 आवास (एचएच) विद्युतीकृत	47.86
जनजातीय कार्य मंत्रालय	बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी)	1000 एमपीसी	873 एमपीसी	433 एमपीसी में कार्य प्रारंभ हो गया।	119.24
	वीडीवीके की स्थापना	500 वीडीवीके	501 वीडीवीके	क्रियाशील: -135 टूल किट वितरित: 280	33.61 (एमओएसडीई के 12.20 करोड़ रुपये सहित)
कुल (करोड़ रु. में)				-	**8369.87**

संबंधित मंत्रालयों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

अनुलग्नक -III

"पीएम-जनमन योजना" के संबंध में श्री हरीभाई पटेल द्वारा दिनांक 28.11.2024 को उठाए गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या †*58 के उत्तर हेतु भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विभाग द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन आधारित आवास सर्वेक्षण के आधार पर पीवीटीजी जनसंख्या का अनुमान (20.11.2024 तक)

क्र.सं.	**राज्य***	**पीवीटीजी जनसंख्या**
1	अंडमान और निकोबार	191
2	आंध्र प्रदेश	492552
3	छत्तीसगढ़	229743
4	गुजरात	153516
5	झारखंड	398952
6	कर्नाटक	57448
7	केरल	29511
8	मध्य प्रदेश	1229201
9	महाराष्ट्र	623143
10	ओडिशा	300436
11	राजस्थान	128456
12	तमिलनाडु	380376
13	तेलंगाना	63194
14	त्रिपुरा	273240
15	उत्तर प्रदेश	3527
16	उत्तराखंड	92233
17	पश्चिम बंगाल	67087
कुल योग		**4522806**

* बिहार और मणिपुर इस अभियान के अंतर्गत शामिल अन्य राज्य हैं।

*****